

## बौद्धिक संपदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन

- नवोन्मेषों का संरक्षण : भाकृअनुप के 23 संस्थानों द्वारा सृजित 45 पेटेंट आवेदनों को भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) में दर्ज किया गया।
- उत्पादों और प्रसंस्करण के लिए दस कॉपीराइट और बारह ट्रेडमार्क आवेदन दर्ज किए गए।
- 56 किस्मों (51 मौजूदा और 5 नई) के संबंध में पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की मंजूरी प्राप्त की गई, जिससे पंजीकृत किस्मों की संचयी संख्या बढ़कर कुल 756 हो गई है।
- परिषद के विभिन्न संस्थानों में 25 कृषि-बिजनेस इनक्यूबेशन (एबीआई) केंद्रों की स्थापना की गई।

## किसानों से संपर्क

- मृदा स्वास्थ्य संरक्षण : 599 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को 1.62 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए।
- 12500 टन से अधिक प्रजनक बीज तथा अन्य नई किस्मों के बीजों का उत्पादन किया गया और दलहनों एवं तिलहनों के लिए अतिरिक्त 97 बीज हब की स्थापना की गई।
- कृषि विज्ञान केंद्रों को सुचारु रूप से चालाने के लिए यूजर इंटरफेस के साथ केवीके पोर्टल की शुरुआत की गई।
- चौतीस नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई, जिसके फलस्वरूप देश में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़कर कुल 676 हो गई है।
- किसानों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 198.67 लाख प्रतिभागियों को शामिल करते हुए 4.69 लाख विस्तार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- दलहनों और तिलहनों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से क्रमशः 1.13 लाख और 76 हजार प्रदर्शन आयोजित किए गए।
- 525 कृषि विज्ञान केंद्रों पर प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया गया।
- 557 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषक समुदाय को समयबद्ध और आवश्यकता आधारित सूचना उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल एडवाइजरी शुरू की गई।
- कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा टेक्नोलॉजी सप्ताह का आयोजन किया गया जिससे 20.60 लाख किसान, कृषक महिलाएं, विस्तार कर्मी, ग्रामीण युवा तथा स्व-सहायता समूहों के सदस्य लाभान्वित हुए।



- कृषि में महिलाओं की भूमिका को सराहने हेतु 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में घोषित किया गया।
- मेरा गांव मेरा गौरव : इस योजना के अन्तर्गत पूरे देश में 13,500 गांवों को अपनाया गया, जिससे 3.5 लाख किसान लाभान्वित हुए।
- जैविक खेती और स्थायी कृषि के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने हेतु नई पहल "पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना" की शुरुआत की गई।
- पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार के द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को प्रोत्साहित किया गया।
- केवीके पोर्टल, केवीके ऐप, किसान मोबाइल एडवाइजरी.केएमएस एसएमएस पोर्टल, KRISHI-ICAR डाटा पोर्टल और मोबाइल ऐप : पूसा कृषि, राइस एक्सपर्ट और चना मित्र इत्यादि की शुरुआत की गई।



## कार्मिक सुधार

- कार्मिक सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीआईएमएस) : एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का स्रजन किया गया।
- पोस्टिंग और स्थानांतरण प्रणाली (पीएटीएस) : पोस्टिंग और स्थानांतरण के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का स्रजन किया गया।
- भाकृअनुप में वरिष्ठ अनुसंधान प्रबंधन के पद को पुनः पारिभाषित करने हेतु स्कोर में बदलाव।
- ई-अभिशासन के लिए पोर्टल सृजित किए गए।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत 18 योजनाएं लाई गईं।
- व्यवसाय में सुगणता : गर्वनमेंट-ई-मार्केट (GeM) के जरिये खरीदारी एवं कैंशलेस भुगतान

## सक्रिय भागीदारी

## “स्वच्छ भारत मिशन”



संकलन : डॉ. वनिता जैन, प्रधान वैज्ञानिक एवं डॉ. मनीष दास, प्रधान वैज्ञानिक

संपर्क करें:

कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूसा, नई दिल्ली-100 012

www.icar.org.in



## भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

## 89वां स्थापना दिवस

16 जुलाई 2017

## प्रमुख उपलब्धियां - 2016-17

वर्ष 2016-17 में 274 मिलियन टन का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन, जिसमें गेहूं (97 मिलियन टन), दलहन (22.4 मिलियन टन), खरीफ (135 मिलियन टन), बागवानी उत्पादन (290 मिलियन टन) जैसी फसलें शामिल हैं।



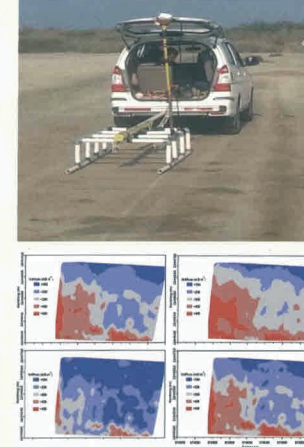


## नई प्रौद्योगिकियों/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमुख उपलब्धियां

- 310 नई फसल किस्में विकसित की गईं, जिनमें अनाज की 155, दलहनों की 43, तिलहनों की 50, रेशा फसलों की 33 और गन्ने की 9 तथा बागवानी फसलों की 51 किस्में शामिल हैं।
- पहली कनोला—टाइप भारतीय सरसों किस्म, पूसा डबल जीरो सरसों 31 (पीडीजेड-1) विकसित की गई। इसके तेल में 2 प्रतिशत से भी कम ईरुसिक अम्ल है और इसके सीड—मील में 30 पीपीएम से भी कम ग्लूकोसाइनोलेट है।
- कपास और सोयाबीन में तंबाकू स्ट्रीक वायरस (टीएसवी) की त्वरित खोज के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई।
- सुपारी उद्यानों में रूट ग्रब्स के प्रबंधन के लिए आईपीएम मॉड्यूल विकसित किया गया।
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए 53 नए फार्म उपकरण और 15 नई फार्म प्रौद्योगिकियां विकसित की गईं।
- मृदापरीक्षक : मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सभी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मृदा जांच प्रक्रिया का उन्नयन किया गया।
- बायोमास के त्वरित विघटन के लिए “रेपो—कम्पोस्ट टेक्नोलॉजी” विकसित की गई।
- तीन नए टीके और 15 डायग्नोस्टिक किटें विकसित की गईं, जिनसे बेहतर पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन की सुनिश्चितता होगी और रोग प्रकोपों का पूर्वानुमान किया जा सकेगा।
- कलॉनिंग के जरिए एक नर भैंस, जिसका नाम हिसार.गौरव है, के जन्म के साथ किसानों के द्वार तक भैंस कलॉनिंग सुविधा पहुंचाई गई।
- औषधि सम्मिश्रण, डायारियोनेक्स—एचएस का व्यवसायीकरण किया गया।
- पशुधन और कुक्कुट की नौ नई नस्लों का पंजीकरण किया गया जिसके कारण पंजीकृत नस्लों की संख्या बढ़कर 160 हो गई है।
- समुद्री खाद्य मछली लेथ्रिनस लेंटजन और सजावटी मछलियों, मारसिया ऐन्थियेस, स्फूडोनथियेस मारिका और रिनकोसाइनेटस डुरबेन्सिस के लिए प्रजनन और बीजोत्पादन हेतु प्रौद्योगिकियां विकसित की गईं।
- सी—वीड्स से मोटापारोधी न्यूट्रास्यूटिकल, (Cadalmint<sup>TM</sup> Ace) उत्पाद विकसित किया गया।
- पैसिफिक सफेद झींगा, पिनेयस वेन्नामेई के पालन की बेहतर प्रबंधन कृषि विधियों पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु वेनामी श्रिम्प ऐप विकसित किया गया।



- कृषिरत महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए एक जेंडर नॉलेज पोर्टल (<http://icar-ciwa.org.in/gks>) विकसित किया गया।
- कृषि में ज्ञान प्रबंधन के लिए भाकृअनुप डाटा रिपोजिट्री “KRISHI” (नवोन्मेषन के लिए ज्ञान आधारित संसाधन सूचना प्रणाली हब) पोर्टल (<http://www.krishi.icar.gov.in>) आरंभ किया गया।
- उन्नत प्रबंधन कार्यनीतियों के लिए भू-भौतिकीय सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी (DUALEM-21) का प्रयोग करते हुए नहर वाले क्षेत्रों के लिए लवणीयता और सोडियम की मैपिंग विकसित की गई।
- डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने हेतु चावल के लिए मोबाइल ऐप राईस एक्सपर्ट (riceXpert) और एक वेब आधारित अनुप्रयोग, अर्थात् पल्स एक्सपर्ट (Pulse Expert) विकसित किया गया।



## उच्च कृषि शिक्षा का सुदृढीकरण

- देश के प्रथम राष्ट्रपती डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी स्मृति में स्कूली छात्रों में उच्च कृषि शिक्षा संबंधी जागरूकता के प्रसार के लिए 3 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया।
- राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय घोषित किया गया।
- रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के तहत चार नए महाविद्यालय शुरू किए गए।
- केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के तहत 6 नए महाविद्यालय शुरू किए गए; जिसके कारण इसके संघटक महाविद्यालयों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है।
- उच्च कृषि शिक्षा की ओर प्रतिभावान छात्रों को आकर्षित करने हेतु राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की गई और स्नातकोत्तर स्तर पर भी इसे लागू किया गया।
- उच्च कृषि शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन: पांचवी संकाय समिति द्वारा अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रमों की पाठ्यक्रम विषयवस्तु में संशोधन कर, उन्हें और अधिक सुसंगत बनाया गया।
- 59 कृषि विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन किया गया।
- 57 कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग प्रक्रिया संपन्न।
- विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (NAHEP) स्वीकृत।
- कृषि और संबद्ध विषयों में स्नातक स्तर की डिग्रियों को प्रोफेशनल घोषित किया गया।



## वैज्ञानिक संपर्क और वैश्विक आउटरीच

- सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीएसटी, डीआरडीओ, इसरो, आईएमडी आदि जैसे अन्य वैज्ञानिक संगठनों के साथ संपर्क स्थापित किया गया।
- अफ़गानिस्तान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना तथा म्यांमार में एक उच्च कृषि शिक्षा केंद्र की स्थापना में सहायता प्रदान की।
- कृषि के लिए एक ब्रिक्स रिसर्च प्लेटफार्म की स्थापना के लिए, जिसका समन्वयन केंद्र भारत में होगा, ब्रिक्स (BRICS) राष्ट्रों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
- इक्रीसेट, इर्री, इकार्डा, आईएफपीआरआई, बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल तथा अन्य कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों के माध्यम से कृषि अनुसंधान का सुदृढीकरण किया गया।

## आत्म-विश्वास और कौशल निर्माण

- कृषि—उद्यमशीलता : उद्यमशीलता और मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए 25 एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर विकसित किए गए।
- कौशल विकास : भारतीय कृषि कौशल परिषद के सहयोग से कौशल विकास के लिए 100 कृषि विज्ञान केंद्रों को चिन्हित किया गया।
- युवा प्रतिभा: कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से उद्यम संबंधी गतिविधियों में 5,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु 25 राज्यों में आर्या (ARYA) परियोजना का कार्यान्वयन किया गया।
- पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्रों (एनईएच) में ‘कंदीय फसलों के मूल्य वर्धन के लिए ग्राम इनक्यूबेशन सेंटर’ की स्थापना मणिपुर में की गई।
- छात्र ग्रामीण उद्यमशीलता एवं जागरूकता विकास योजना (Student Ready) का कार्यान्वयन : 11000 से अधिक अंडर ग्रेजुएट (UG) छात्र लाभान्वित हुए।

